स्वदेश

लखनऊ - मुख्य संस्करण
14 May 2026 | Page - 6

सनातन को मिटाने की राजनीति पर फिर बवाल

राजेश कुमरावत

भारत की सांस्कृतिक चेतना और हजारों वर्षों पुरानी परंपरा रहे सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु की राजनीति एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। पूर्व मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा विधानसभा में 'सनातन को खत्म कर देना चाहिए' जैसी टिप्पणी ने देशभर में नई बहस छेड़ दी है। इससे पहले वर्ष 2023 में भी वे सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से कर चुके हैं। उस समय भी बयान को लेकर व्यापक विरोध हुआ था, लेकिन अब दोबारा उसी प्रकार की भाषा ने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या हिंदू आस्था पर टिप्पणी करना कुछ राजनीतिक दलों की स्थायी रणनीति बन चुकी है? तमिलनाडु को लंबे समय से सामाजिक समरसता और धर्मनिरपेक्ष राजनीति का उदाहरण बताया जाता रहा है। राज्य में लगभग 87 प्रतिशत आबादी हिंदू समाज से जुड़ी हुई है, जबकि ईसाई समुदाय की संख्या लगभग 6 प्रतिशत बताई जाती है। ऐसे प्रदेश में सनातन धर्म को 'समाप्त करने' जैसी बात कहना करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला विषय बन गया है। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या किसी अन्य धर्म के विरुद्ध भी कोई नेता इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकता है? यदि कोई सार्वजनिक मंच से इस्लाम या ईसाई धर्म को 'मिटाने' की बात कहे, तो क्या राजनीतिक दलों और तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग की प्रतिक्रिया इतनी ही शांत रहती? यही वह प्रश्न है जो अब देशभर में बहस का विषय बना हुआ है। इस पूरे विवाद में तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की चुप्पी भी चर्चा के केंद्र में है। विधानसभा में दिए गए इस बयान के बाद मुख्यमंत्री की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री होने के नाते उनसे अपेक्षा थी कि वे सभी धर्मों और आस्थाओं के सम्मान की बात करते। लेकिन सार्वजनिक रूप से उनकी ओर से कोई कड़ा विरोध न आने के कारण विपक्ष और हिंदू संगठनों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। जोसेफ विजय और उदयनिधि स्टालिन के पुराने संबंधों को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। तमिल फिल्म कुरुवी में उदयनिधि स्टालिन निर्माता-दिग्दर्शक की भूमिका से जुड़े थे, जबकि विजय मुख्य अभिनेता थे। ऐसे में राजनीतिक समीकरणों और व्यक्तिगत संबंधों को लेकर भी कई प्रकार की चर्चाएं सामने आ रही हैं। हालांकि लोकतंत्र में व्यक्तिगत संबंध अलग विषय हैं, लेकिन जब करोड़ों लोगों की आस्था का मामला हो, तब जनता निष्पक्ष और स्पष्ट प्रतिक्रिया की अपेक्षा करती है। इतिहास गवाह है कि सनातन धर्म को समाप्त करने या उसकी जड़ों को कमजोर करने के अनेक प्रयास हुए, लेकिन भारत की सांस्कृतिक चेतना सदैव मजबूत होकर उभरी। सनातन केवल पूजा-पद्धति नहीं, बल्कि 'वसुधैव कुटुम्बकम्' और 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' जैसे सार्वभौमिक विचारों पर आधारित जीवन-दर्शन है। यही कारण है कि इसे केवल एक धार्मिक पहचान के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मा के रूप में देखा जाता है। तमिलनाडु की इस पूरी घटना ने हिंदू समाज के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है। जब राज्य की लगभग 87 प्रतिशत आबादी सनातन परंपरा से जुड़ी हो, तब उसी समाज की आस्था पर खुले मंच से प्रहार किए जाएं और सत्ता मौन बनी रहे, तो यह केवल राजनीतिक विषय नहीं रह जाता, बल्कि सामाजिक चेतना का प्रश्न बन जाता है। आज आवश्यकता केवल प्रतिक्रिया देने की नहीं, बल्कि संगठित वैचारिक जागरण की है। हिंदू समाज को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में संख्या केवल आंकड़ा नहीं होती, बल्कि सांस्कृतिक आत्मविश्वास और वैचारिक सजगता का प्रतीक भी होती है। **(लेखक पत्रकार एवं समसामयिक विश्लेषक)**

..., त्याग और समर्पण की निधि है - आचार्य श्रीराम शर्मा

स्वदेश

रीवा - नव स्वदेश
14 May 2026 | Page - 6

सऊदा अरब, सयुक्त अरब पर पड़ता ह। भारत जस एव सामारक शाक्त इन ताना का कला समाक्षक ह)

राजनीति और सनातन

सनातन को मिटाने की राजनीति पर फिर बवाल

राजेश कुमरावत

भारत की सांस्कृतिक चेतना और हजारों वर्षों पुरानी परंपरा रहे सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु की राजनीति एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। पूर्व मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा विधानसभा में 'सनातन को खत्म कर देना चाहिए' जैसी टिप्पणी ने देशभर में नई बहस छेड़ दी है। इससे पहले वर्ष 2023 में भी वे सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से कर चुके हैं। उस समय भी बयान को लेकर व्यापक विरोध हुआ था, लेकिन अब दोबारा उसी प्रकार की भाषा ने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या हिंदू आस्था पर टिप्पणी करना कुछ राजनीतिक दलों की स्थायी रणनीति बन चुकी है? तमिलनाडु को लंबे समय से सामाजिक समरसता और धर्मनिरपेक्ष राजनीति का उदाहरण बताया जाता रहा है। राज्य में लगभग 87 प्रतिशत आबादी हिंदू समाज से जुड़ी हुई है, जबकि ईसाई समुदाय की संख्या लगभग 6 प्रतिशत बताई जाती है। ऐसे प्रदेश में सनातन धर्म को 'समाप्त करने' जैसी बात कहना करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला विषय बन गया है। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या किसी अन्य धर्म के विरुद्ध भी कोई नेता इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकता है? यदि कोई सार्वजनिक मंच से इस्लाम या ईसाई धर्म को 'मिटाने' की बात कहे, तो क्या राजनीतिक दलों और तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग की प्रतिक्रिया इतनी ही शांत रहती? यही वह प्रश्न है जो अब देशभर में बहस का विषय बना हुआ है। इस पूरे विवाद में तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की चुप्पी भी चर्चा के केंद्र में है। विधानसभा में दिए गए इस बयान के बाद मुख्यमंत्री की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री होने के नाते उनसे अपेक्षा थी कि वे सभी धर्मों और आस्थाओं के सम्मान की बात करते। लेकिन सार्वजनिक रूप से उनकी ओर से कोई कड़ा विरोध न आने के कारण विपक्ष और हिंदू संगठनों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। जोसेफ विजय और उदयनिधि स्टालिन के पुराने संबंधों को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। तमिल फिल्म कुरुवी में उदयनिधि स्टालिन निर्माता-दिग्दर्शक की भूमिका से जुड़े थे, जबकि विजय मुख्य अभिनेता थे। ऐसे में राजनीतिक समीकरणों और व्यक्तिगत संबंधों को लेकर भी कई प्रकार की चर्चाएं सामने आ रही हैं। हालांकि लोकतंत्र में व्यक्तिगत संबंध अलग विषय हैं, लेकिन जब करोड़ों लोगों की आस्था का मामला हो, तब जनता निष्पक्ष और स्पष्ट प्रतिक्रिया की अपेक्षा करती है। इतिहास गवाह है कि सनातन धर्म को समाप्त करने या उसकी जड़ों को कमजोर करने के अनेक प्रयास हुए, लेकिन भारत की सांस्कृतिक चेतना सदैव मजबूत होकर उभरी। सनातन केवल पूजा-पद्धति नहीं, बल्कि 'वसुधैव कुटुम्बकम्' और 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' जैसे सार्वभौमिक विचारों पर आधारित जीवन-दर्शन है। यही कारण है कि इसे केवल एक धार्मिक पहचान के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मा के रूप में देखा जाता है। तमिलनाडु की इस पूरी घटना ने हिंदू समाज के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है। जब राज्य की लगभग 87 प्रतिशत आबादी सनातन परंपरा से जुड़ी हो, तब उसी समाज की आस्था पर खुले मंच से प्रहार किए जाएं और सत्ता मौन बनी रहे, तो यह केवल राजनीतिक विषय नहीं रह जाता, बल्कि सामाजिक चेतना का प्रश्न बन जाता है। आज आवश्यकता केवल प्रतिक्रिया देने की नहीं, बल्कि संगठित वैचारिक जागरण की है। हिंदू समाज को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में संख्या केवल आंकड़ा नहीं होती, बल्कि सांस्कृतिक आत्मविश्वास और वैचारिक सजगता का प्रतीक भी होती है।

(लेखक पत्रकार एवं समसामयिक विश्लेषक)

स्वदेश

सांध्य - सांध्यवार्ता
14 May 2026 | Page - 4

। सऊदी अरब, संयुक्त अरब पर पड़ता है। भारत जस एवं सामरिक शक्ति इन तीनों का कला समीक्षक है)

राजनीति और सनातन

सनातन को मिटाने की राजनीति पर फिर बवाल

राजेश कुमरावत

भारत की सांस्कृतिक चेतना और हजारों वर्षों पुरानी परंपरा रहे सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु की राजनीति एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। पूर्व मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा विधानसभा में 'सनातन को खत्म कर देना चाहिए' जैसी टिप्पणी ने देशभर में नई बहस छेड़ दी है। इससे पहले वर्ष 2023 में भी वे सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से कर चुके हैं। उस समय भी बयान को लेकर व्यापक विरोध हुआ था, लेकिन अब दोबारा उसी प्रकार की भाषा ने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या हिंदू आस्था पर टिप्पणी करना कुछ राजनीतिक दलों की स्थायी रणनीति बन चुकी है? तमिलनाडु को लंबे समय से सामाजिक समरसता और धर्मनिरपेक्ष राजनीति का उदाहरण बताया जाता रहा है। राज्य में लगभग 87 प्रतिशत आबादी हिंदू समाज से जुड़ी हुई है, जबकि ईसाई समुदाय की संख्या लगभग 6 प्रतिशत बताई जाती है। ऐसे प्रदेश में सनातन धर्म को 'समाप्त करने' जैसी बात कहना करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला विषय बन गया है। राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या किसी अन्य धर्म के विरुद्ध भी कोई नेता इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकता है? यदि कोई सार्वजनिक मंच से इस्लाम या ईसाई धर्म को 'मिटाने' की बात कहे, तो क्या राजनीतिक दलों और तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग की प्रतिक्रिया इतनी ही शांत रहती? यही वह प्रश्न है जो अब देशभर में बहस का विषय बना हुआ है। इस पूरे विवाद में तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की चुप्पी भी चर्चा के केंद्र में है। विधानसभा में दिए गए इस बयान के बाद मुख्यमंत्री की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री होने के नाते उनसे अपेक्षा थी कि वे सभी धर्मों और आस्थाओं के सम्मान की बात करते। लेकिन सार्वजनिक रूप से उनकी ओर से कोई कड़ा विरोध न आने के कारण विपक्ष और हिंदू संगठनों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। जोसेफ विजय और उदयनिधि स्टालिन के पुराने संबंधों को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। तमिल फिल्म कुरुवी में उदयनिधि स्टालिन निर्माता-दिग्दर्शक की भूमिका से जुड़े थे, जबकि विजय मुख्य अभिनेता थे। ऐसे में राजनीतिक समीकरणों और व्यक्तिगत संबंधों को लेकर भी कई प्रकार की चर्चाएं सामने आ रही हैं। हालांकि लोकतंत्र में व्यक्तिगत संबंध अलग विषय हैं, लेकिन जब करोड़ों लोगों की आस्था का मामला हो, तब जनता निष्पक्ष और स्पष्ट प्रतिक्रिया की अपेक्षा करती है। इतिहास गवाह है कि सनातन धर्म को समाप्त करने या उसकी जड़ों को कमजोर करने के अनेक प्रयास हुए, लेकिन भारत की सांस्कृतिक चेतना सदैव मजबूत होकर उभरी। सनातन केवल पूजा-पद्धति नहीं, बल्कि 'वसुधैव कुटुम्बकम्' और 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' जैसे सार्वभौमिक विचारों पर आधारित जीवन-दर्शन है। यही कारण है कि इसे केवल एक धार्मिक पहचान के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मा के रूप में देखा जाता है। तमिलनाडु की इस पूरी घटना ने हिंदू समाज के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है। जब राज्य की लगभग 87 प्रतिशत आबादी सनातन परंपरा से जुड़ी हो, तब उसी समाज की आस्था पर खुले मंच से प्रहार किए जाएं और सत्ता मौन बनी रहे, तो यह केवल राजनीतिक विषय नहीं रह जाता, बल्कि सामाजिक चेतना का प्रश्न बन जाता है। आज आवश्यकता केवल प्रतिक्रिया देने की नहीं, बल्कि संगठित वैचारिक जागरण की है। हिंदू समाज को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में संख्या केवल आंकड़ा नहीं होती, बल्कि सांस्कृतिक आत्मविश्वास और वैचारिक सजगता का प्रतीक भी होती है।

(लेखक पत्रकार एवं समसामयिक विश्लेषक)

ना, त्याग और समर्पण की निधि है - आचार्य श्रीराम शर्मा

‘सनातन को मिटाने’ की राजनीति पर फिर बवाल

उदयनिधि के बयान और मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की चुप्पी पर देशभर में उठे सवाल

भारत की सांस्कृतिक चेतना और हजारों वर्षों पुरानी परंपरा रहे सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु की राजनीति एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। पूर्व मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा विधानसभा में ‘सनातन को खत्म कर देना चाहिए’ जैसी टिप्पणी ने देशभर में नई बहस छेड़ दी है। इससे पहले वर्ष 2023 में भी वे सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से कर चुके हैं। उस समय भी बयान को लेकर व्यापक विरोध हुआ था, लेकिन अब दोबारा उसी प्रकार की भाषा ने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या हिंदू आस्था पर टिप्पणी करना कुछ राजनीतिक दलों की स्थायी रणनीति बन चुकी है?

तमिलनाडु को लंबे समय से सामाजिक समरसता और धर्मनिरपेक्ष राजनीति का उदाहरण बताया जाता रहा है। राज्य में लगभग 87 प्रतिशत आबादी हिंदू समाज से जुड़ी हुई है, जबकि ईसाई समुदाय की संख्या लगभग 6 प्रतिशत बताई जाती है। ऐसे प्रदेश में सनातन धर्म को ‘समाप्त करने’ जैसी बात कहना करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला विषय बन गया है।

राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या किसी अन्य धर्म के विरुद्ध भी कोई नेता इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकता है? यदि कोई सार्वजनिक मंच से इस्लाम या ईसाई धर्म को ‘मिटाने’ की बात कहे, तो क्या राजनीतिक दलों और तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग की प्रतिक्रिया इतनी ही शांत रहती? यही वह प्रश्न है जो अब देशभर में बहस का विषय बना हुआ है।

इस पूरे विवाद में तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की चुप्पी भी चर्चा के केंद्र में है। विधानसभा में दिए गए इस बयान के बाद मुख्यमंत्री की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री होने के नाते उनसे अपेक्षा थी कि वे सभी धर्मों और आस्थाओं के सम्मान की बात करते। लेकिन सार्वजनिक रूप से उनकी ओर से कोई कड़ा विरोध न आने के कारण विपक्ष और हिंदू संगठनों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।

जोसेफ विजय और उदयनिधि स्टालिन के पुराने संबंधों को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। तमिल फिल्म कुरुवी में उदयनिधि स्टालिन

निर्माता-दिग्दर्शक की भूमिका से जुड़े थे, जबकि विजय मुख्य अभिनेता थे। ऐसे में राजनीतिक समीकरणों और व्यक्तिगत संबंधों को लेकर भी कई प्रकार की चर्चाएं सामने आ रही हैं। हालांकि लोकतंत्र में व्यक्तिगत संबंध अलग विषय हैं, लेकिन जब करोड़ों लोगों की आस्था का मामला हो, तब जनता निष्पक्ष और स्पष्ट प्रतिक्रिया की अपेक्षा करती है।

इतिहास गवाह है कि सनातन धर्म को समाप्त करने या उसकी जड़ों को कमजोर करने के अनेक प्रयास हुए, लेकिन भारत की सांस्कृतिक चेतना सदैव मजबूत होकर उभरी। सनातन केवल पूजा-पद्धति नहीं, बल्कि ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ और ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ जैसे सार्वभौमिक विचारों पर आधारित जीवन-दर्शन है। यही कारण है कि इसे केवल एक धार्मिक पहचान के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मा के रूप में देखा जाता है।

तमिलनाडु की इस पूरी घटना ने हिंदू समाज के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है। जब राज्य की लगभग 87 प्रतिशत आबादी सनातन परंपरा से जुड़ी हो, तब उसी समाज की आस्था पर खुले मंच से प्रहार किए जाएं और सत्ता मौन बनी रहे, तो यह केवल राजनीतिक विषय नहीं रह जाता, बल्कि सामाजिक चेतना का प्रश्न बन जाता है। आज आवश्यकता केवल प्रतिक्रिया देने की नहीं, बल्कि संगठित वैचारिक जागरण की है। हिंदू समाज को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में संख्या केवल आंकड़ा नहीं होती, बल्कि सांस्कृतिक आत्मविश्वास और वैचारिक सजगता का प्रतीक भी होती है।

जिस सनातन ने हजारों वर्षों तक भारत की सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को जीवित रखा, उसी सनातन के विरुद्ध यदि बार-बार अपमानजनक शब्द बोले जा रहे हैं और बहुसंख्यक समाज मौन रह जाता है, तो यह आत्ममंथन का विषय है। तमिलनाडु में एक ईसाई मुख्यमंत्री का सनातन विरोधी बयान पर चुप रहना भी राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का विषय बन गया है। सवाल किसी व्यक्ति विशेष के धर्म का नहीं, बल्कि उस संवैधानिक दायित्व का है, जहां सत्ता में बैठे व्यक्ति से हर आस्था के सम्मान की अपेक्षा की जाती है।

आज आवश्यकता है कि हिंदू समाज भावनात्मक प्रतिक्रिया से आगे बढ़कर वैचारिक रूप से जागृत हो, अपनी सांस्कृतिक जड़ों को समझे और लोकतांत्रिक माध्यमों से अपनी आस्था के सम्मान के लिए सजग बने। क्योंकि इतिहास यह बताता है कि जो समाज अपनी संस्कृति और परंपरा के प्रति उदासीन हो जाता है, उसकी पहचान धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगती है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वोटबैंक की राजनीति में धार्मिक प्रतीकों और आस्थाओं को निशाना बनाना लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए उचित संकेत नहीं माना जा सकता। लोकतंत्र में असहमति और आलोचना का अधिकार सभी को है, लेकिन किसी आस्था के ‘समूल नाश’ की भाषा सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक मर्यादा देनों पर प्रश्नचिह्न खड़े करती है।

देशभर में उठ रही प्रतिक्रियाओं के बीच अब यह सवाल प्रमुखता से पूछा जा रहा है कि क्या स्टालिन परिवार इस बयान पर देश से माफी मांगेगा, या फिर यह विवाद भी राजनीतिक बयानबाजी बनकर सीमित रह जाएगा। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि सनातन धर्म को लेकर दिया गया यह बयान तमिलनाडु की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है।

समसामयिकी लेख:
राजेश कुमरावत ‘सार्थक’

भोजशाला का निर्णय : केवल एक परिसर नहीं, सांस्कृतिक आत्मा की पुनर्प्रतिष्ठा

धार की पवित्र भूमि से इतिहास, आस्था और न्याय के संगम का संदेश, वर्षों की प्रतीक्षा के बाद न्यायालय ने स्वीकारा भोजशाला का आध्यात्मिक स्वरूप

राजेश कुमशावत सार्थक
दैनिक उज्जैन रजत

धार की पावन धरा पर स्थित भोजशाला केवल पत्थरों से निर्मित कोई प्राचीन संरचना नहीं, बल्कि भारत की ज्ञान परंपरा, आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक स्मृतियों का जीवंत प्रतीक रही है। सदियों से यहां मां वाग्देवी की आराधना, संस्कृत की स्वरधारा और भारतीय संस्कृति का आलोक प्रवाहित होता रहा। समय के उतार-चढ़ाव, संघर्षों और विवादों के बीच भी समाज की आस्था ने इस पवित्र स्थल को अपने हृदय में जीवित रखा। आज जब न्यायालय ने भोजशाला के मूल स्वरूप को स्वीकार करते हुए ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है, तब यह केवल एक कानूनी विजय नहीं, बल्कि सनातन चेतना, सांस्कृतिक स्वाभिमान और ऐतिहासिक सत्य की पुनर्प्रतिष्ठा का क्षण बन गया है। यह निर्णय आने वाली पीढ़ियों को यह स्मरण कराएगा कि भारत की आत्मा उसकी संस्कृति, श्रद्धा और ज्ञान परंपरा में बसती है।

धार भोजशाला पर आया यह निर्णय केवल एक न्यायिक आदेश नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना, सनातन परंपरा और ऐतिहासिक स्मृतियों के पुनर्जागरण का प्रतीक बनकर सामने आया है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ द्वारा धार स्थित भोजशाला को देवी वाग्देवी अर्थात माता सरस्वती का मंदिर मानते हुए सुनाया गया निर्णय वर्षों से चल रहे एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संघर्ष का महत्वपूर्ण पड़ाव है। न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की वैज्ञानिक रिपोर्टों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और सांस्कृतिक साक्ष्यों के आधार पर यह माना कि भोजशाला प्राचीन काल में संस्कृत शिक्षा और देवी वाग्देवी की उपासना का केंद्र रही है। न्यायालय ने हिंदू समाज को पूजा का अधिकार प्रदान करते हुए परिसर में नमाज की व्यवस्था को समाप्त करने तथा मुस्लिम पक्ष के लिए वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराने की बात कही है।

यह निर्णय केवल एक इमारत या विवादित परिसर तक सीमित नहीं है। यह उस सांस्कृतिक चेतना का प्रश्न था, जो सदियों से भारतीय समाज की स्मृतियों में जीवित रही। भोजशाला भारत की उस गौरवशाली परंपरा का प्रतीक रही है, जहां ज्ञान को देवत्व प्राप्त था, जहां सरस्वती केवल पूजनीय देवी नहीं बल्कि राष्ट्र की बौद्धिक आत्मा मानी जाती थीं।

धार नगरी का नाम आते ही परमार वंश के महान सम्राट राजा भोज का स्मरण स्वाभाविक रूप से होता है। राजा भोज केवल एक शासक नहीं थे, बल्कि वे भारतीय ज्ञान परंपरा, साहित्य, स्थापत्य, आयुर्वेद, ज्योतिष और संस्कृत संस्कृति के महान संरक्षक थे। कहा जाता है कि उनके शासनकाल में धार विद्या और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बनी। भोजशाला उसी गौरवशाली परंपरा की जीवंत धरोहर मानी जाती रही है। इतिहासकारों और सांस्कृतिक अध्येताओं के अनुसार भोजशाला में संस्कृत शिक्षा, शास्त्रार्थ और विद्वानों की सभाएं आयोजित होती थीं। यहां मां वाग्देवी की उपासना के साथ ज्ञान की साधना का वातावरण था। इसलिए भोजशाला का प्रश्न केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता और ऐतिहासिक स्मृति से जुड़ा हुआ विषय था।

भोजशाला को लेकर वर्षों तक न्यायालयों में संघर्ष चलता रहा। अनेक सामाजिक संगठनों, संतों, विद्वानों और स्थानीय समाज ने इसे केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में देखा। हिंदू समाज के भीतर यह भावना लंबे समय से रही कि इतिहास के अनेक उतार-चढ़ावों में भारत की सांस्कृतिक पहचान को धूमिल करने के प्रयास हुए, किंतु समाज की स्मृति ने उन प्रतीकों को जीवित रखा।

भोजशाला का संघर्ष इसी सांस्कृतिक स्मृति का संघर्ष था। यह उस विश्वास का संघर्ष था कि सत्य और इतिहास को लंबे समय तक दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। वर्षों तक न्यायालय में दस्तावेज, पुरातात्विक साक्ष्य, स्थापत्य शैली और ऐतिहासिक अभिलेख प्रस्तुत किए गए। अंततः न्यायालय ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर अपना निर्णय दिया।

इस निर्णय का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं है। यह भारत में सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्थलों की पहचान के प्रश्न को भी नए सिरे से सामने लाता है। लंबे समय से यह बहस चलती रही कि क्या भारत अपने इतिहास, अपने प्रतीकों और अपनी सांस्कृतिक स्मृतियों को उसी संवेदनशीलता के साथ देख पा रहा है, जिसकी अपेक्षा एक प्राचीन सभ्यता से की जाती है?

भोजशाला पर आया निर्णय इस बात का संकेत है कि न्यायालय ऐतिहासिक तथ्यों, वैज्ञानिक सर्वेक्षणों और सांस्कृतिक साक्ष्यों को गंभीरता से सुन रहा है। यह उन लोगों के लिए भी एक संदेश है, जिन्होंने वर्षों तक शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखी। जब समाज इस निर्णय को ÷ सनातन की विजय ÷ कहता है, तो उसका अर्थ किसी अन्य समुदाय की पराजय नहीं होना चाहिए। सनातन की मूल आत्मा समरसता, ज्ञान, सहअस्तित्व और सत्य की खोज में निहित है। इस निर्णय को उसी परिपक्वता और संतुलन के साथ देखने की आवश्यकता है। यह विजय उस सांस्कृतिक आत्मविश्वास की विजय है, जिसने सदियों के संघर्ष के बाद भी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा।

जी यानी दांत और मसूड़े से व्यक्ति की पहचान

ऐसा एक ऐसी
ाध्यम से मुख
जबड़े आदि के
ी पहचान और
सूचना प्राप्त हो
ाओं को लेकर
ाते हैं जहां शव
सी व्यक्ति की
भी रखा जा सकता है। फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी इस विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके माध्यम से विभिन्न प्राकृतिक आपदा, बड़े हादसे, दुर्घटना, विस्फोट जैसे मामलों में प्रमाणिक सूचना संकलित की जा सकती है। कई अपराधों, हत्या, बच्चों के साथ
सटीक पहचान मिलती है जिससे उनके परिजनों को सूचना देना संभव होता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान समय में इस वैज्ञानिक शाखा का काफी उपयोग किया जा रहा है। फोरेंसिक विशेषज्ञ जांच प्रक्रिया के दौरान दांत व जबड़े की संरचना, एक्स-रे बाइक मार्क
जांच के मामले में भी नवीन तकनीकी सुविधाओं की आवश्यकता महसूस की जा रही है और फोरेंसिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के माध्यम से विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। कुल मिलाकर फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी

Edit Annotate Fill & Sign Convert All

‘सनातन को मिटाने’ की राजनीति पर फिर बवाल

उदयनिधि के बयान और मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की चुप्पी पर देशभर में उठे सवाल

भारत की सांस्कृतिक चेतना और हजारों वर्षों पुरानी परंपरा रहे सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु की राजनीति एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। पूर्व मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा विधानसभा में ‘सनातन को खत्म कर देना चाहिए’ जैसी टिप्पणी ने देशभर में नई बहस छेड़ दी है। इससे पहले वर्ष 2023 में भी वे सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से कर चुके हैं। उस समय भी बयान को लेकर व्यापक विरोध हुआ था, लेकिन अब दोबारा उसी प्रकार की भाषा ने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या हिंदू आस्था पर टिप्पणी करना कुछ राजनीतिक दलों की स्थायी रणनीति बन चुकी है?

तमिलनाडु को लंबे समय से सामाजिक समरसता और धर्मनिरपेक्ष राजनीति का उदाहरण बताया जाता रहा है। राज्य में लगभग 87 प्रतिशत आबादी हिंदू समाज से जुड़ी हुई है, जबकि ईसाई समुदाय की संख्या लगभग 6 प्रतिशत बताई जाती है। ऐसे प्रदेश में सनातन धर्म को ‘समाप्त करने’ जैसी बात कहना करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला विषय बन गया है।

राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या किसी अन्य धर्म के विरुद्ध भी कोई नेता इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकता है? यदि कोई सार्वजनिक मंच से इस्लाम या ईसाई धर्म को ‘मिटाने’ की बात कहे, तो क्या राजनीतिक दलों और तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग की प्रतिक्रिया इतनी ही शांत रहती? यही वह प्रश्न है जो अब देशभर में बहस का विषय बना हुआ है।

इस पूरे विवाद में तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की चुप्पी भी चर्चा के केंद्र में है। विधानसभा में दिए गए इस बयान के बाद मुख्यमंत्री की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री होने के नाते उनसे अपेक्षा थी कि वे सभी धर्मों और आस्थाओं के सम्मान की बात करते। लेकिन सार्वजनिक रूप से उनकी ओर से कोई कड़ा विरोध न आने के कारण विपक्ष और हिंदू संगठनों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।

जोसेफ विजय और उदयनिधि स्टालिन के पुराने संबंधों को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। तमिल फिल्म कुरुवी में उदयनिधि स्टालिन

निर्माता-दिग्दर्शक की भूमिका से जुड़े थे, जबकि विजय मुख्य अभिनेता थे। ऐसे में राजनीतिक समीकरणों और व्यक्तिगत संबंधों को लेकर भी कई प्रकार की चर्चाएं सामने आ रही हैं। हालांकि लोकतंत्र में व्यक्तिगत संबंध अलग विषय हैं, लेकिन जब करोड़ों लोगों की आस्था का मामला हो, तब जनता निष्पक्ष और स्पष्ट प्रतिक्रिया की अपेक्षा करती है।

इतिहास गवाह है कि सनातन धर्म को समाप्त करने या उसकी जड़ों को कमजोर करने के अनेक प्रयास हुए, लेकिन भारत की सांस्कृतिक चेतना सदैव मजबूत होकर उभरी। सनातन केवल पूजा-पद्धति नहीं, बल्कि ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ और ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ जैसे सार्वभौमिक विचारों पर आधारित जीवन-दर्शन है। यही कारण है कि इसे केवल एक धार्मिक पहचान के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मा के रूप में देखा जाता है।

तमिलनाडु की इस पूरी घटना ने हिंदू समाज के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है। जब राज्य की लगभग 87 प्रतिशत आबादी सनातन परंपरा से जुड़ी हो, तब उसी समाज की आस्था पर खुले मंच से प्रहार किए जाएं और सत्ता मौन बनी रहे, तो यह केवल राजनीतिक विषय नहीं रह जाता, बल्कि सामाजिक चेतना का प्रश्न बन जाता है। आज आवश्यकता केवल प्रतिक्रिया देने की नहीं, बल्कि संगठित वैचारिक जागरण की है। हिंदू समाज को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में संख्या केवल आंकड़ा नहीं होती, बल्कि सांस्कृतिक आत्मविश्वास और वैचारिक सजगता का प्रतीक भी होती है।

जिस सनातन ने हजारों वर्षों तक भारत की सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को जीवित रखा, उसी सनातन के विरुद्ध यदि बार-बार अपमानजनक शब्द बोले जा रहे हैं और बहुसंख्यक समाज मौन रह जाता है, तो यह आत्ममंथन का विषय है। तमिलनाडु में एक ईसाई मुख्यमंत्री का सनातन विरोधी बयान पर चुप रहना भी राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का विषय बन गया है। सवाल किसी व्यक्ति विशेष के धर्म का नहीं, बल्कि उस संवैधानिक दायित्व का है, जहां सत्ता में बैठे व्यक्ति से हर आस्था के सम्मान की अपेक्षा की जाती है।

आज आवश्यकता है कि हिंदू समाज भावनात्मक प्रतिक्रिया से आगे बढ़कर वैचारिक रूप से जागृत हो, अपनी सांस्कृतिक जड़ों को समझे और लोकतांत्रिक माध्यमों से अपनी आस्था के सम्मान के लिए सजग बने। क्योंकि इतिहास यह बताता है कि जो समाज अपनी संस्कृति और परंपरा के प्रति उदासीन हो जाता है, उसकी पहचान धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगती है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वोटबैंक की राजनीति में धार्मिक प्रतीकों और आस्थाओं को निशाना बनाना लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए उचित संकेत नहीं माना जा सकता। लोकतंत्र में असहमति और आलोचना का अधिकार सभी को है, लेकिन किसी आस्था के ‘समूल नाश’ की भाषा सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक मर्यादा दोनों पर प्रश्नचिह्न खड़े करती है।

देशभर में उठ रही प्रतिक्रियाओं के बीच अब यह सवाल प्रमुखता से पूछा जा रहा है कि क्या स्टालिन परिवार इस बयान पर देश से माफी मांगेगा, या फिर यह विवाद भी राजनीतिक बयानबाजी बनकर सीमित रह जाएगा। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि सनातन धर्म को लेकर दिया गया यह बयान तमिलनाडु की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है।

समसामयिकी लेख:
राजेश कुमरावत ‘सार्थक’

नव भारत
संस्थापक : स्व. रामगोपाल माहेश्वरी | प्रेरणा स्रोत : स्व. प्रफुल्ल माहेश्वरी

विकसित भारत 2047 : क्रियान्वयन की ओर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई साढ़े चार घंटे लंबी मंत्रिपरिषद बैठक केवल प्रशासनिक समीक्षा भर नहीं थी, बल्कि यह उस भारत की रूपरेखा तय करने का प्रयास थी, जिसे सरकार वर्ष 2047 तक 'विकसित राष्ट्र' के रूप में देखना चाहती है. आजादी के शताब्दी वर्ष को लक्ष्य बनाकर केंद्र सरकार जिस प्रकार दीर्घकालिक नीति, संरचनात्मक सुधार और प्रशासनिक बदलावों पर फोकस कर रही है, उससे स्पष्ट है कि 'विकसित भारत 2047' अब केवल राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि शासन का केंद्रीय विजन बन चुका है. बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का यह संदेश महत्वपूर्ण है कि 'जो हो गया, उसे पीछे छोड़िए, अब भविष्य पर फोकस कीजिए.' यह कथन दरअसल भारतीय शासन व्यवस्था की उस मानसिकता को बदलने का संकेत है, जो लंबे समय तक तात्कालिक राजनीति और अल्पकालिक योजनाओं तक सीमित रही. मोदी सरकार अब मंत्रालयों से अगले दो-तीन वर्षों की नहीं, बल्कि अगले दो दशकों की सोच के साथ काम करने की अपेक्षा कर रही है. यही कारण है कि सभी मंत्रालयों को कानून, नियम, नीति और कार्यशैली—इन चार स्तरों पर सुधारों का रोडमैप प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए.

इस बैठक का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इज आफ लिविंग पर जोर रहा. पिछले एक दशक में सरकार ने इज अआफ डूइंग बिजनेस के जरिए निवेश और कारोबार का माहौल सुधारने की कोशिश की, लेकिन अब फोकस सीधे नागरिक जीवन की गुणवत्ता पर है. आम आदमी को सरकारी दफ्तरों, कागजी प्रक्रियाओं और नौकरशाही की जटिलताओं से राहत देना ही असली सुशासन की कसौटी बनेगा. प्रधानमंत्री द्वारा फाइलों के त्वरित निपटारे और अनावश्यक देरी समाप्त करने पर दिया गया जोर इसी सोच को दर्शाता है. 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' का मंत्र भी इस बैठक का केंद्रीय संदेश रहा. इसका अर्थ केवल सरकारी हस्तक्षेप कम करना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जहां सरकार नियंत्रणकर्ता से अधिक सहयोगी की भूमिका निभाए. डिजिटल गवर्नेंस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ऑनलाइन सेवाएं और पारदर्शी प्रक्रियाएं इसी मॉडल की आधारशिला हैं. यदि यह सोच ईमानदारी से जमीन पर उतरी, तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार और लालफीताशाही में बड़ी कमी आ सकती है.

हालांकि, विकसित भारत का सपना केवल सरकारी बैठकों और प्रस्तुतियों से पूरा नहीं होगा. इसके लिए राज्यों, निजी क्षेत्र, शिक्षा संस्थानों और समाज की समान भागीदारी जरूरी होगी. भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो रोजगार, कौशल विकास, तकनीकी नवाचार, कृषि सुधार, ऊर्जा सुरक्षा और न्यायिक दक्षता जैसे क्षेत्रों में ठोस परिणाम देने होंगे. केवल आर्थिक वृद्धि दर पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि सामाजिक समानता और संस्थागत मजबूती भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी. विदेश मंत्री एस. जयशंकर द्वारा प्रधानमंत्री की पांच देशों की यात्रा और मिडिल ईस्ट संकट पर दी गई जानकारी यह भी बताती है कि विकसित भारत का विजन अब घरेलू सीमाओं तक सीमित नहीं है. वैश्विक अस्थिरता, ऊर्जा संकट और भू-राजनीतिक तनावों के बीच भारत को अपनी अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित रखना होगा. आने वाले वर्षों में भारत की वैश्विक भूमिका और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ने वाली हैं.

स्पष्ट है कि सरकार अब 'विजन मोड' में प्रवेश कर चुकी है. चुनौती यही है कि यह विजन कागजों से निकलकर गांव, शहर और आम नागरिक के जीवन में कितना बदलाव ला पाता है. क्योंकि विकसित भारत का वास्तविक अर्थ केवल बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि बेहतर जीवन, सक्षम व्यवस्था और आत्मविश्वासी नागरिक भी है.

सनातन को मिटाने की राजनीति पर फिर बवाल

राजेश कुमरावत सार्थक

> राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि वोटबैंक की राजनीति में धार्मिक प्रतीकों और आस्थाओं को निशाना बनाना लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए उचित संकेत नहीं माना जा सकता. लोकतंत्र में असहमति और आलोचना का अधिकार सभी को है, लेकिन किसी आस्था के समूल नाश की भाषा सामाजिक सौहार्द और संवैधानिक मर्यादा दोनों पर प्रश्नचिह्न खड़े करती है. देशभर में उठ रही प्रतिक्रियाओं के बीच अब यह सवाल प्रमुखता से पूछा जा रहा है कि क्या स्टालिन परिवार इस बयान पर देश से माफी मांगेगा, या फिर यह विवाद भी राजनीतिक बयानबाजी बनकर सीमित रह जाएगा. फिलहाल इतना स्पष्ट है कि सनातन धर्म को लेकर दिया गया यह बयान तमिलनाडु की राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है.

भारत की सांस्कृतिक चेतना और हजारों वर्षों पुरानी परंपरा रहे सनातन धर्म को लेकर तमिलनाडु की राजनीति एक बार फिर विवादों के केंद्र में है. पूर्व मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा विधानसभा में सनातन को खत्म कर देना चाहिए जैसी टिप्पणी ने देशभर में नई बहस छेड़ दी है. इससे पहले वर्ष 2023 में भी वे सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से कर चुके हैं. उस समय भी बयान को लेकर व्यापक विरोध हुआ था, लेकिन अब दोबारा उसी प्रकार की भाषा ने यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या हिंदू आस्था पर टिप्पणी करना कुछ राजनीतिक दलों की स्थायी रणनीति बन चुकी है?

तमिलनाडु को लंबे समय से सामाजिक समरसता और धर्मनिरपेक्ष राजनीति का उदाहरण बताया जाता रहा है. राज्य में लगभग 87 प्रतिशत आबादी हिंदू समाज से जुड़ी हुई है, जबकि ईसाई समुदाय की संख्या लगभग 6 प्रतिशत बताई जाती है. ऐसे प्रदेश में सनातन धर्म को समाप्त करने जैसी बात कहना करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला विषय बन गया है. राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सबसे अधिक चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या किसी अन्य धर्म के विरुद्ध भी कोई नेता इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकता है? यदि कोई सार्वजनिक मंच से इस्लाम या ईसाई धर्म को मिटाने की बात कहे, तो क्या राजनीतिक दलों और तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग की प्रतिक्रिया इतनी ही शांत रहती?

यही वह प्रश्न है जो अब देशभर में बहस का विषय बना हुआ है. इस पूरे विवाद में तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की चुप्पी भी चर्चा के केंद्र में है. विधानसभा में दिए गए इस बयान के बाद मुख्यमंत्री की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री होने के नाते उनसे अपेक्षा थी कि वे सभी धर्मों और आस्थाओं के सम्मान की बात करते. लेकिन सार्वजनिक रूप से उनकी ओर से कोई कड़ा विरोध न आने के कारण विपक्ष और हिंदू संगठनों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. जोसेफ विजय और उदयनिधि स्टालिन के पुराने संबंधों को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं. तमिल फिल्म कुरुवी में उदयनिधि स्टालिन निर्माता-दिग्दर्शक की भूमिका से जुड़े थे, जबकि विजय मुख्य अभिनेता थे. ऐसे में राजनीतिक समीकरणों और व्यक्तिगत संबंधों को लेकर भी कई प्रकार की चर्चाएं सामने आ रही हैं.

हालांकि लोकतंत्र में व्यक्तिगत संबंध अलग विषय हैं, लेकिन जब करोड़ों लोगों की आस्था का मामला हो, तब जनता निष्पक्ष और स्पष्ट प्रतिक्रिया की अपेक्षा करती है. इतिहास गवाह है कि सनातन धर्म को समाप्त करने या उसकी जड़ों को कमजोर करने के अनेक प्रयास हुए, लेकिन भारत की सांस्कृतिक चेतना सदैव मजबूत होकर उभरी. सनातन केवल पूजा-पद्धति नहीं, बल्कि वसुधैव कुटुम्बकम् और सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे सार्वभौमिक विचारों पर आधारित जीवन-दर्शन है. यही कारण है कि इसे केवल एक धार्मिक पहचान के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मा के रूप में देखा जाता है. तमिलनाडु की इस पूरी घटना ने हिंदू समाज के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है. जब राज्य की लगभग 87 प्रतिशत आबादी सनातन परंपरा से जुड़ी हो, तब उसी समाज की आस्था पर खुले मंच से प्रहार किए जाएं और सत्ता मौन बनी रहे, तो यह केवल राजनीतिक विषय नहीं रह जाता, बल्कि सामाजिक चेतना का प्रश्न बन जाता है.

आज आवश्यकता केवल प्रतिक्रिया देने की नहीं, बल्कि संगठित वैचारिक जागरण की है. हिंदू समाज को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में संख्या केवल आंकड़ा नहीं होती, बल्कि सांस्कृतिक आत्मविश्वास और वैचारिक सजगता का प्रतीक भी होती है. जिस सनातन ने हजारों वर्षों तक भारत की सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को जीवित रखा, उसी सनातन के विरुद्ध यदि बार-बार अपमानजनक शब्द बोले जा रहे हैं और बहुसंख्यक समाज मौन रह जाता है, तो यह आत्ममंथन का विषय है. तमिलनाडु में एक ईसाई मुख्यमंत्री का सनातन विरोधी बयान पर चुप रहना भी राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का विषय बन गया है.

(लेखक -वरिष्ठ पत्रकार एवं समसामयिक विश्लेषक, सामाजिक-सांस्कृतिक विषयों के सजग हस्ताक्षर)